

(ख) राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने यह भी सूचित किया है कि प्राथमिक स्तर की हिन्दी की सभी पुस्तकों का मूल्यांकन प्रगति पर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Schemes for Child Welfare

1455. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are not paying due attention to certain schemes pertaining to Child Welfare;

(b) what is the role of NIPCCD in formulation and implementation of programmes concerning children;

(c) whether it is a fact that the top posts of NIPCCD have remained vacant for a long time; and

(d) if so, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) WITH ADDITIONAL CHARGE OF MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT, (KUMARI MAMATA BANLRJEE) : (a) No, Sir.

(b) The role of National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) in the formulation and implementation of programmes is as under :

- (i) To conduct, promote, sponsor and collaborate in research and evaluation studies in Child Development;
- (ii) To review programmes for children in the light of the National Policy for Children;
- (iii) To review voluntary action in socin' development;

(iv) To organise and sponsor training programme, orientation courses and Workshops/seminars/conferences for personnel in government service and voluntary sector engaged in child development;

(v) To identify problems and needs in the area of child development;

(vi) To advise the Central and State Governments and its agencies, and various other institutions, in the further development and implementation of policies for child development.

(c) There are three top posts in NIPCCD. One is the post of Director and the other two posts of Additional Director. Two posts of Additional Director are filled but the post of Director, NIPCCD is lying vacant since 1st June, 1989. The senior-most Additional Director is holding additional charge of the post of Director.

(d) Vigorous efforts are on to select a person of proven merit for the post of Director. Two interviews have also been held. No suitable person has, however, been found so far. The Government is presently holding consultation with various experts to identify a person of proven merit and siature who will head the Institute.

Crimes against children

1456. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the increasing number of children being kidnapped and being put to cruel and nefarious use ;

(b) what steps Government propose to take to curb such crimes against children ;

(c) whether there is any proposal to conduct specific survey about the number of children not living with their family members ;

(d) whether Government have given any encouragement to NGOs to participate in

identifying and rescuing children being forcibly held and used ; and

(e) whether any efforts have been made by Government to use media to create awareness amongst the public on this problem ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) WITH ADDITIONAL CHARGE OF MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (KUMARI MAMATA BANERJEE) : (a) to (e) Information is being collected and when received will be laid on the Table of the House.

केन्द्रीय विद्यालय थास्को-डी-नाभा प्रिंसिपल के विरुद्ध शिकायतें

1457. श्री महेन्द्र सिंह लाठर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय सं० 1 मंगुरहिल्स थास्को-डी-नाभा (गोआ) के कर्मचारियों ने विद्यालय के प्रिंसिपल के विरुद्ध कई शिकायतें की हैं तथा इसकी जानकारी इस संगठन के निदेशक और आयुक्त को भी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कई संसद सदस्यों ने भी सरकार से इस प्रिंसिपल के विरुद्ध जांच कराये जाने और कर्मचारियों को शोषण से राहत दिलाये जाने का अनुरोध किया है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए हैं और 1990 से लेकर आज तक दोषी अधिकारी के विरुद्ध उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि विद्यालय की वि० प्र० सं० के अध्यक्ष ने आयुक्त को सम्बोधित अपने दिनांक 27-12-91 के पत्र में प्रशासनिक और वित्तीय स्वरूप की तथाकथित अनियमितताओं पर प्रकाश डाला तथा वर्ग 'ग' कर्मचारियों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति वर्ग 'घ' कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति तथा प्रधानाचार्य की स्कूल से अवकाश-अनुपस्थिति के लिए तथाकथित रूप से पुरिटकरण की मांग की है।

(ग) सहायक-आयुक्त (बम्बई) जिसके आधिकार क्षेत्र में यह विद्यालय आता है ने आरोपों की प्रारंभिक जांच की। रिपोर्ट की इस सहाय जांच को जा रही है।

उत्तर प्रदेश में डिग्री कालेज

1458. श्री ईश्वर दत्त यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उत्तर प्रदेश में डिग्री कालेज स्थापित किए जाने में सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?
मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग नए कालेज स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान नहीं करता है। कालेज सामान्यतया राज्य सरकारों अथवा पंजीकृत संसद्-इंटियों या न्यास द्वारा स्थापित किए जाने हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ निर्धारित मानदंडों के अनुसार पुस्तकों, पत्रिकाओं और उपस्कर की खरीद, स्टाफ की नियुक्ति और शैक्षिक और छात्रावास भवन के निर्माण के लिए आयोग के पास उपलब्ध संसाधनों के भीतर मौजूदा पाठ कालेजों को विकास अनुदान प्रदान करता है।